

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3048
उत्तर देने की तारीख 07.08.2025

स्टार्ट अप इकोसिस्टम पर संगोष्ठी

3048. श्री भोजराज नागः

श्रीमती संैद्या रायः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

श्री बसवराज बोम्मईः

श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

श्री रोडमल नागरः

श्री गोडम नागेशः

सुश्री कंगना रनौतः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

श्री मुकेश राजपूतः

श्री नव चरण माझीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर आयोजित संगोष्ठी के क्या उद्देश्य हैं,
- (ख) अनुसूचित जनजाति से जुड़े उद्यमियों के लिए नवगठित वैचर कैपिटल फंड की कुल राशि कितनी है और उसकी संरचना तथा आवंटन का ब्यौरा क्या है;
- (ग) जनजातीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए परामर्श हेतु चयनित संस्थानों के नाम क्या हैं;
- (घ) उक्त संगोष्ठी के अंतर्गत आपूर्ति शुंखलाओं को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और जनजातीय स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक बाजारों तक पहुँच बढ़ाने हेतु प्रस्तावित कदम सहित प्रमुख सिफारिशें क्या हैं,
- (ङ) राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के टीएसपी क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

- (च) विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त राज्यों में जिन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया गया है, उनका नाम और जिलावार ब्यौरा क्या हैं,
- (छ) उक्त राज्यों में स्टार्टअप योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजातियों के लोगों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
- (ज) क्या सरकार का देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल ब्लॉकों में ऐसे आयोजन या इनक्यूबेशन अभियान आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
- (झ) उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए वित्तपोषण, प्रशिक्षण और डिजिटल अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उडके)

(क) से (झ) मंत्रालय ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित देश भर में अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की निधि के साथ 10 फरवरी, 2024 को 'अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष' (वीसीएफ-एसटी) योजना शुरू की। यह कोष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत ऋण-उन्मुख वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) श्रेणी-II के रूप में जारी किया गया है। यह योजना आईएफसीआई वीसीएफ लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अब तक, दो जनजातीय कंपनियों को 8.41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है - एक तेलंगाना में (5.00 करोड़ रुपये) और एक छत्तीसगढ़ में (3.41 करोड़ रुपये)।

इस योजना के अंतर्गत, आईएफसीआई वीसीएफ लिमिटेड ने 28 जनवरी, 2025 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख उद्यम पूंजीपतियों और प्रभाव निवेशकों को जनजातीय उद्यमियों के उत्थान, जनजातीय-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में निवेश को उत्प्रेरित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतिभागियों में इंडियन एंजेल नेटवर्क, इन्फो एज, आईवीसीए, आविष्कार कैपिटल, ग्रोथकैप वैंचर्स, विल्ग्रो, एसकेआई कैपिटल, आईएफसीआई वैंचर और सिडबी के पूर्व अधिकारी शामिल थे। संगोष्ठी की प्रमुख सिफारिशों में गुणवत्तापूर्ण जनजातीय उद्यमों का निर्माण, ग्राम स्तर पर लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जनजातीय सशक्तिकरण और नवाचार के लिए उच्च क्षमता वाले विशिष्ट उद्योगों, जैसे कृषि, हस्तशिल्प और सतत विकास, की पहचान करना और नवोन्मेषी एवं प्रभावशाली क्षेत्रों में निवेश को दिशा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) मॉडल को बढ़ावा देना शामिल था।
